

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] No. 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 14, 2016/चैत्र 25, 1938 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 2016/CHAITRA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है ।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
- '(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;'।
- 3. उक्त नियम के नियम 4 में,---
 - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।
- (1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1)

1847 GI/2016

- (1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।" ;
- (ख) उपनियम (2) में "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) उपनियम (3) में "किसी विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- (घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,–
 - (क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति ;
 - (ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किऐ जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।";

- (इ.) उपनियम (5) में "विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए" शब्द रखे जाएंगे;
- (च) उपनियम (6) के स्थान पर, "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों के नियम 7 में,---
- (क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।
- (2क) उप नियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा ।";
- (ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग(विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।"।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(viक) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;"।
- 6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "(vii) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।"।
- 7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन ।"।

- 8. उक्त नियम के नियम 12 में,---
- (क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।
- (4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।
- (4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।";
- (ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमश: रखे जाएंगे।
- 9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व** (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी।
- (2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए गए निवारात्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलितयों से संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"।
- 10. उक्त नियम के नियम 15 में.—
- (i) उपनियम (1) में,—
- (क) "उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;
- (ii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।
- 11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन:
 - (1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:--
 - (i) मुख्यमंत्री या प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

- (ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे) ;
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद्, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;
- (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;
- (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव।
- (2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।"
- 12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंत:स्थापित किए जांएगे।
- 13. उक्त नियम के, नियम 17क के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंत:स्थापित किए जांएगे।
- 14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध-।

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदंड

राहत रााश के लिए मापदड		
क्रम सं	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । पीड़ित व्यक्ति को संदाय
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना	निम्नानुसार किया जाए:
	[(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	क्षति करने, अपमानित या क्ष्ट्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव	(एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और
	इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
4.	जुतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अर्धिनियम की	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50
7.	धारा 3(1)(घ)]	प्रतिशत;
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए
0.	करना, मुंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा	अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40
	3(1)(s.)]	प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के
	3(1)(4.)]	लिए 25 प्रतिशत।
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । जहां आवश्यक हो वहां
	धारा 3(1)(च)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत	खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा
	ू वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा	वापस लौटाई जाएगी । पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय
	3(1)(퍽.)]	किया जाएगा:

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा
9.	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समपर्ण का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)]	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	पर 25 प्रतिशत ।
21.	शत्रुता, घृणा स वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैंकना या फैंकने का प्रयत्न करना ।[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।
		मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i)प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिए दंड [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;
		' '
		(iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत ।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्वस्त्र करने के	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की	जाएगा :
	अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25
		प्रतिशत ।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 40 प्रतिशत ।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 40 प्रतिशत ।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ	जाएगा :
	पठित धारा 3(2)(νक)]	(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के
		पश्चात् 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा	जाएगा :
	3(2)(v雨)]	(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के
		पश्चात् 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25
		प्रतिशत ।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया
	कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	जाएगा :
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया
		जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च
		किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की
	II.	

उसके स्थानीय तिष्ठा के परायशं से दिवा प्रशिक्ती होते । विश्वव की जाने वाली प्रवृत्ति की मामुपादिक अस्तियों को मृत्तिन नरने के लिए किया महिन्दुरे के पान जाता ही जाए मुंच स्विक्त रहें के लिए किया महिन्दुरे के पान जाता ही जाए पहुंच रखने में बाघा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)] विश्वव रखने में बाघा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)] (1) प्रथम मुम्ना निर्माद (एफकाईआर) कमन पर 25 प्रतिवत; (1) प्रथम मुम्ना निर्माद (एफकाईआर) कमन पर 25 प्रतिवत; (1) नियम त्यावाल द्वारा अभिकृत व्यक्ति को बार माच पश्चीच हहतार रुपए और रृजरों के अधिकार के घरवावर्तन का कर्च। संवत निमानुतार किया वाएगा; (1) प्रथम मुम्ना निर्माद (एफकाईआर) कमन पर 25 प्रतिवत; (1) नियम त्यावाल द्वारा अभिकृत व्यक्ति को बोयमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिवत; (1) नियम त्यावाल द्वारा अभिकृत व्यक्ति को बोयमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिवत; (1) नियम त्यावाल द्वारा अभिकृत व्यक्ति को बोयमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिवत; (1) अवस स्थान पर स्थन वा उद्दर्शन के अधिकार के बारा पर सुकार वा उद्दर्शन के अधिकार के बारा पर सुकार वा उद्दर्शन के अधिकार के बारा पर मुकार किया का उपयोग के प्रतिवत्त वा सरकारी वा चे पर रृज प्रतिवत्त वा सरकारी वा चे पर सुकार वा उद्दर्शन के अधिकार के अधिकार पर मुकार वा उद्दर्शन के अधिकार वा स्थान के अधिकार पर मुकार के पर वा अधिकृत व्यक्ति को चोयमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिवत (1) अवस त्यावाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति को चोयमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिवत वा अधिकृत के साथ समान्त के आधार पर सुकार के आधार पर पह का माम्यव समान्त के आधार पर प्रतिवत वा क्रावाल द्वारा अधिकृत के साथ समान्त के आधार पर सुकार के आधार पर सुकार के साथ समान्त के आधार पर सुकार के साथ समान्त के आधार पर सुकार के साथ समान्त के आधार पर स्वचित राज सामान सुकार के साथ साथना के अधार सुकार के साथ साथना के अधार पर संवित्त राज सामान सुकार के साथ साथन द्वार के साथ साथ सुकार के साथ साथ सुकार के साथ साथ सुकार के साथ साथ सुकार के सुका			
वृद्धित करते के लिए विजय सबिस्ट्रेट के पाय जमा की वाए। जीक समागम के किसी स्थान से गुजरों के किसी केट्रिजर अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयों करने या उस पर पर्टूच रखने में याश्रा पहुँचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(या)] अधिकार के प्रत्यान के जोर पाय पहुँच रखने से याश्रा पहुँचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(या)] अधिकार के प्रत्यान के अधिकार के प्रत्यान करने या उस पर (ग्रं) प्रवस्त मुक्ता रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ग्रं) प्रवस्त मुक्ता रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ग्रं) निजरे ल्यावालक द्वारा अधिकृत क्यति को दोपानिद्व किए जाने पर 25 प्रतिशत अधिकार राज्य संक्रम या संक्रम क्यान पर 25 प्रतिशत अधिकार राज्य संक्रम या संक्रम क्यान या रहर के अधिकार केट्रिजर राज्य संक्रम या संक्रम क्यान पर स्थान या रहर के अधिकार केट्रिजर राज्य संक्रम या संक्रम क्यान पर स्थान या रहर के अधिकार केट्रिजर राज्य संक्रम या संक्रम क्यान या रहर के अधिकार केट्रिजर राज्य संक्रम या संक्रम क्यान या रहर के अधिकार केट्रिजर राज्य संक्रम या संक्रम का स्थान का स्थान का स्थान (अ) अंग की सामाल्य सम्पति या जल्य के नाथ समानता के आधार पर क्रियरनात या अधान भूमि या किसी नित्र आपित, सरता, कुआ, टेक्र, हैज, नव या अव्यक क्यान या त्राहों के चार, विस्ती केट्रालिय हैज, हैज, नव या अव्यक क्यान या त्राहों के चार, विस्ती केट्रालिय हैज, हैज, नव या अव्यक क्यान या त्राहों के चार, विस्ती केट्रालिय हैज, किसी सहक या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)) क्या स्थान पर के अपर पर प्रचित राज्य स्था संक्रम के वा रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)) (ग्रं) सार्यक्रम क्यान पर के अधिकार पर सरवित राज्य स्था स्वात के अपर पर प्रचिति राज्य स्था स्वात के स्था पर पर सरवित राज्य स्था स्वात स्था स्था स्था स्था के स्याव के स्था स्था स्था स्था है । (अ) सार्यक्रम क्यान पर के प्रवस स्था स्था स्था है । (अ) सार्यक्रम क्यान पर के प्रवस्त स्था स्था के स्था स्था स्था स्था स्था स्था है । (अ) सार्यक्रम क्यान के स्था स्था स्था स्था है । (अ) सार्यक्रम क्यान पर के स्था स्था स्था स्था है । (अ) सार्यक्रम क्यान पर के स्था सारव के स्था सारव के स्था सारव है स्था सी स्था सारव के स्था सारव है । (अ) सार			
अर्थ संक्रित समापन के किसी स्थान से गुजर के किसी कड़िजर अधिकार से स्वाधित राज्य सरकार या गंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पृष्टेन रचने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3(1)(म))			
हनकर या लोक समायम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुँच रखने में बाधा पहुँचान (अधिनियम की धारा 3(1)(स)) श्री के अधिकार के प्रत्यावर्गन का खर्च । संवाद निमानुनार किया वाएगा: () प्रथम मुचना रिपोर्ट (एकआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत: (ii) निवर्ष लाखालब द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोरानिव्यक्त की धारा 3(1)(य)) 35. पृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए सजबूर करना (अधिनियम सबिध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रथानन द्वारा गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए सजबूर करना (अधिनियम सबिध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रथानन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल वा टहरने के अधिकार के सहात और पीडित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर रुह का पुन: सनिर्माण, यदि विनिष्ट हो या है। सेवाद निम्मानुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान के सामनुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान हो सामनुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान सामनुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान के सामनुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान किया आपणा हो। यह हो स्थान के सामनुसार किया आपणा हो। यह हो स्थान के सामनुसार के आधार पर उपयोग को या किया सामनुसार के सामनुसार के सामनुसार के साम सामनुसार के आधार पर उपयोग को या किया सामनुसार के सामनुसार हो सामनुसार के सामनुसार के सामनुसार हो सामनुसार के सामनुसार हो सामनुसार के सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार के सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार हो सामनुसार के सामनुसार के सामनुसार के सामनुसार के सामनुसार			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)] के अधिकार के घरवावर्तन का खर्च । संदाय निमानुसार किया जाएता: (i) प्रथम सूचना रिगोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत: (ii) निवाले न्यावालय द्वारा अभिवृत्त व्यक्ति को दोषानिद्ध निर्णालने पर 25 प्रतिशत: विद्या अभिवृत्त व्यक्ति को दोषानिद्ध निर्णालने पर 25 प्रतिशत: विद्या अभिवृत्त व्यक्ति को दोषानिद्ध निर्णालने पर 25 प्रतिशत: विद्या वा निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम में बिरा पर 3(1)(या)] विद्या वा निवास के अव्यव्यक्ति को एक लाख रुपण की राइत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः सनिर्णाण, यदि विनिष्ट हो स्था है. सेवाय निर्णालम हिया आएला: (i) अव्यव्यक्ति के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचत विद्या को आरोप पत्र भेज होए, वाने पर 50 प्रतिशत: (ii) व्यावालक को अरोप पत्र भेज होए, वाने पर 50 प्रतिशत: (iii) अव्यव्यक्ति के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित (iii) अव्यव्यक्ति के संबंध में, किसी रीते होए जाने पर 25 प्रतिशत: (iii) अव्यव्यक्ति के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित (iii) अव्यव्यक्ति के साथ समानता के आधार पर पर परित कर के साथ समानता के आधार पर पर परिते के सिर पर प्रयोग के साथ समानता के आधार पर पर परिते के सिर पर प्रयोग के साथ समानता के आधार पर पर परिते के सिर पर प्रयोग के साथ समानता के आधार पर अधिवृति राज्य समानता के आधार पर अधिवृत्त राज्य समानता के आधार पर अधिवृत्त राज्य समानता के साथा साथा स्था स्था के प्रयोग वा वित अध्य समानता स्था समानता के साथा साथा साथा साथा साथा साथा साथा साथ	34.		
अध्यम सुचना रिपोर्ट (एकआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) स्वायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभिकृत व्यक्ति को दोषसिद्ध किए वाने पर 25 प्रतिशत मृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की श्री शरा 3(1)(य)] श्री शरा 3(1)(य)] श्री शरा 3(1)(य)] श्री शरा 3(1)(य)] श्री शरा वा निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम मंत्री श्रीवित व्यक्ति के स्थान पर स्थान या इहरने के अधिकार की बहाती और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकार खा संघ प्रकृत स्थान महाने पा तथा तथा जाएगा: (i) प्रथम मुचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत: (ii) अवर न्यायालय द्वारा अभिकृत व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत: (ii) अवर न्यायालय द्वारा अभिकृत व्यक्ति को दोषसिद्ध कित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति मं अनुस्ति को शारा, अरना, कुंजा, हैक, हौज, नल वा अल्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी निवस स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी, धारा, अरना, कुंजा, हैक, हौज, नल वा अल्य कल कल कल के आपर पर उपयोग को या परिव का अल्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या परिव का अल्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या परिव का अल्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या परिव का उपयोग समानता के आधार पर उपयोग को या परिव का उपयोग समानता के आधार पर उपयोग सरकार या स्था परिव का अल्य का स्थान पर का अल्य कल कल कल कल के अल्य स्थान परिव का अल्य कल कल कल कर कर के आधार पर स्थावित कर सरकार या स्था परिव को आधार पर स्थावित का सम्या या स्था का उपयोग समानता के आधार पर उपयोग समानता के आधार पर उपयोग समानता स्था स्था के स्था परिव का अल्य कल कल कल कर स्था स्था परिव का जावा है; (iii) उठ प्रतिशत जब अभिकृत को अवर स्थावालय द्वार सोचित कर साथ होता साथ होता की स्था की स्था जावा है; (iii) उठ प्रतिशत जब अभिकृत को अवर स्थावालय को भेजा जावा है; (iii) उपयोग स्थाप स्था स्था स्था से स्थाप स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था		•	_
(i) प्रथम मुचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को अरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निषक न्यायालय को अरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निषक न्यायालय को अरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; विशे धारा 3(1)(य)) 35. सृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनयम जी धारा 25 प्रतिशत । जविका राज्य मरकार या गंज राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनयम जी बार 125 प्रतिशत । प्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या टहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित ब्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा मरकार या निवास के अन्य पर पृत्र का मरकार या निवास के अन्य पर पृत्र का मरकार या निवास के अन्य पर पृत्र का मरकार या निवास के अन्य पर प्रशासन वा मरकार या निवास के अस्था पर पर 50 प्रतिशत । (ii) अबर न्यायालय हारा अभिवृत्त व्यक्ति को दोषसिद किए जाने पर 25 प्रतिशत का अस्था पर उपयोग को या प्रतिश्र तथा स्थान मुस्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर किसी तथा अप के साथ समानता के आधार पर किसी तथा अप के साथ समानता के अधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हीज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी मुक्त या स्थान के अधार पर उपयोग को या पिड़ित को एक लाख रुपए की राहता सदाय निमानुसार किया वाहा हो हो एक लाख रुपए की राहता सदाय निमानुसार किया वाहा हो		पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	-
(ii) न्यायालय को आरोप पत्र मेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) निक्तं न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोपसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत । गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए सजबूर करना [अधिनियम संग्रित राज्य सरकार वा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल वा ठहरने के अधिकार की बढ़ाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख ठूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः सनिर्माण, यदि विनिष्ट हो स्था है। संवाय निम्नानुसार किया जाएगा : () प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) अवर न्यायालय को आरोप पत्र मेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय हो आरोप पत्र मेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; होज, नल या अन्य जल स्थान या अन्य के साथ समानता के आधार पर के किसतान या अन्या जन स्थान सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर प्रयोग को या अन्य के किसी सहक या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)) (आ) मार्यवितिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए क्ष्य पहनना या वारात के वीरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना वा वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))) (आ) मार्यवितिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए क्ष्य पहनना या वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना वा वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना वा वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना वा वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना वा वारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))			•
(III) निवले त्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत । गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए सजबूर करना [अधिनियस की धारा 3(1)(य)] श्री धारा 3(1)(य) श्री धारा			
किए जाने पर 25 प्रतिशत वृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास का स्थान पर स्थल या उहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुन: सनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है : संदाव निस्तृतार किया जाएगा : (1) प्रथम मूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत : (11) अवर न्यायालय होरा अभियुक्त व्यक्ति को दोपसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत : (2) अंत्र की सामान्य सम्पत्ति या अल्य के साथ समानता के आधार पर कित्रस्ता नया स्थान मूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंजा, टैंक, हीज, तल या अल्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी नदी, धारा, झरना, कुंजा, टैंक, हीज, तल या अल्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सहक या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सहक या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या सोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वळ पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान पोड़े की सवारी या किसी अल्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या सोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वळ पहनना या बारात विकालना या बारात के दौरान घोड़ की सवारी या किसी अल्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या सोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वळ पहनना या बारात के दौरान घोड़ की सवारी या किसी अल्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या सोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वळ पहनना या बारात के दौरान घोड़ की सवारी या किसी अल्य बाहन की सवारी करना [अधिनय कि सवारी करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष । संवाय निम्नानुसार किया जाएगा: (अ) अपने स्वत्तिक स्थानों पर साइकिल या सोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वळ पहनना या बारात के दौरान घोड़ की सवारी या किसी अल्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या स्वत्तिक करना वार स्वत्तिक करना वार विक्तिक करना वार वार की सवारी के प्रत्तिक करना वार विक्तिक करना वार वार विक्तिक करना वार वार की सवार विक्तिक करना वार वार विक्तिक करन			(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
35. गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोंड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(य)] संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अल्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाती और पीड़ित ज्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन: संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है, संद्वाय निमानुसार किया जाएगा:			(iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
श्री धारा 3(1)(व)] श्री मा या निवास के अल्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीढ़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन. सिनामण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सुचना रिपोर्ट (एफआईआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोधसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अल्य के साथ समानता के आधार पर किसिनान या थमशान भूमि का अल्य के साथ समानता के आधार पर किसिनान या थमशान भूमि या किसी नदी; धारा, झरना, कुंआ, टैंक, होज, नल या अल्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक पिवहन, किसी नदी धारा, झरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा, झरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा, झरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा, अरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा, अरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा, अरना, कुंआ, टैंक, किसी नदी धारा अरना, किसी आहम या सम्पत्ति के अधार पर स्थितित राज्य समकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रणासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (()) प्रथम मुचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वख्य पहनना या बारात के बौरान थोड़े की सवारी या किसी अन्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(वक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वख्य पहनना या बारात के बौरान थोड़े की सवारी या किसी अन्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(वक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वख्य पहनना या बारात है इसार को पाल को स्थान किया करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुरोप। संयाय निमानुसार किया जाएगा: (()) प्रथम सुचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (()) 50 प्रतिशत जब अरियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा सुराय बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुरोप। संयाय निमानुसार किया जाएगा: (()) प्रथम सुचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (()) 50 प्रतिशत जब अरियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा के निमारी की राज्य निमानुसार किया जाएगा: (()) प्रथम सुचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (()) 50 प्रतिशत जब अरियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा के नी पर सार्वजन के सार्वजन के सार्			किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
की बहाली और पीडित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन: संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम स्चना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत तः (ii) न्यायालय को आरोप पत्र मेज विए जाने पर 50 प्रतिशत तः (iii) अवर त्यायालय को आरोप पत्र मेज विए जाने पर 50 प्रतिशत तः (iii) अवर त्यायालय को आरोप पत्र मेज विए जाने पर 50 प्रतिशत तः (iii) अवर त्यायालय को आरोप पत्र मेज विए जाने पर 50 प्रतिशत तः (iii) अवर त्यायालय को आरोप पत्र मेज विए जाने पर 50 प्रतिशत तः (iii) अवर त्यायालय को वाध डालना या निवारित करना — (iii) अवे की सामान्य सम्पत्ति संग्राधनों किश्रमतान या श्रमशान को आधार पर अपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नदाने के घाटा, किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, विस्ति प्राच्य स्थान के आधार पर उपयोग की या अन्य जल स्थान या नहाने के घाटा, विस्ति के घाटा, विस्ति के घाटा, विस्ति विस्ति के घाटा, विस्ति के घाट	35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह,
तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिथत हः (ii) ज्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिथत हः (iii) अवर त्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिथत के संदर्थ में किसी रीति में अनुमूचित जाति या अनुमूचित (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति सं अन्य के साथ समानता के आधार पर कविस्तान या श्मशान कृति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कविस्तान या श्मशान होज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान यो जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात वारात के तौरान यो किरान पान किरान या में पान विकाल राय सं या राय के प्रथम स्वार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के तौरान यो किरान यो किरान यो वारात के तौरान यो किरान यो वारात के तौरान यो किरान यो वारात विकालना या वारात के तौरान यो किरान यो वारात विकालना यो वारात के तौरान यो किरान यो वारात विकालना यो वारात के तौरान यो किरान यो वारात विकालना यो वारात के तौरान यो किरान यो के प्रथम स्वर राय के प्रथम स्वर राय के प्रथम स्वर राय के त्र पर यो विकाल यो यो राय स्वर किरान यो विकाल राय यो राय स्वर के प्रथम स्वर राय के प्रथम स्वर राय के प्रयास स्वर राय के प्रथम स्वर राय के प्रथम स्वर राय वाल के अभियुक्त के अवर स्वयालय द्वार (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर स्वयालय द्वार यो विकाल यो अपित विकाल यो अपित स्वर स्वर यो विकाल यो		की धारा 3(1)(य)]	ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार
त्या है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) अवर त्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर त्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। 36.			की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत
(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशतः (iii) व्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशतः (iii) अवर त्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशतः (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना वा क्षा की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना वा कृतीदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य केत्र पर का अनुतोप। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन: संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो
(ii) त्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अत्रर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत । 36.			गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
(iii) अवर त्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। 36.			(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
किए जाने पर 25 प्रतिशत । विस्नितिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित अधार पर अधित की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर क्षिनी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुकत को अवर न्यायालय द्वारा या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या वारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] वाहन की सवारी करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोप । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोप । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय को भेजा जाता है ;			(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
36. निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति के मदस्य को बांधा डालना या निवारित करना — (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर क्रियस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साडकिल या मोटर साडकिल पर सबार होना या जूतादि या नए क्ख पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साडकिल या मोटर साडकिल पर सबार होना या जूतादि या नए क्ख पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साडकिल या मोटर साडकिल पर सबार होना या जूतादि या नए क्ख पहनना या बारात के दौरान घोड़ो की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) धार्यजनिक स्थानों पर साडकिल या मोटर साडकिल पर सवार होना या जूतादि या नए क्ख पहनना या बारात के दौरान घोड़ो की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) धार्यजनिक स्थानों पर साडकिल या मोटर साडकिल पर सवार होना या जूतादि या नए क्ख पहनना या वारात किसी अन्य वाहन की सवारी करना आधि पर स्थान किसी अन्य वाहन की सवारी करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संवाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय होरा			(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
जनजाति के सदस्य को बांधा डालना या निवारित करना — (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान यो जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान थोड़ की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोप । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: ()) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिथत; (ii) 50 प्रतिथत जब असियुक्त को अवर न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिथत जब असियुक्त को अवर न्यायालय होरा			किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
जनजाति के सदस्य को बांधा डालना या निवारित करना — (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान यो जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान धारा 3(1)(यक)(आ)] (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जुतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान थोड़ की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोप । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: ()) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिथत; (ii) 50 प्रतिथत जब असियुक्त को अवर न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिथत जब असियुक्त को अवर न्यायालय होरा	36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित	(अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान
कब्रिस्तान या श्रमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हैंज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए बस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य बाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा है;			भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या
कब्रिस्तान या श्रमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हैंज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (अ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए बस्त्र पहनना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा है;		(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर	किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल
हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुकत को अवर न्यायालय द्वारा वोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात विकालना या वारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या वारात निकालना या वारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या
किसी महक या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)] सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुकत को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए बस्च पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य
किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
(i) प्रथम मूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			-
(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुकत को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			,
(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर। (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा विकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
(आ) सार्वजिनक स्थानों पर साइिकल या मोटर साइिकल पर सवार होना या जूतािद या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] धारा 3(1)(यक)(आ)] वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुकत को अवर न्यायालय द्वारा
या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] धारा 3(1)(यक)(आ)] वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			दोषसिद्ध किये जाने पर।
घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)] धारा 3(1)(यक)(आ)] वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;		(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना	(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर
धारा 3(1)(यक)(आ)] बाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा		घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की	·
अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा		धारा 3(1)(यक)(आ)]	
(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा			
			-
			दोषसिद्ध किये जाने पर।
(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों (इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा		* *	
के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य यक्तियों के लिए			
			खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी
उनमें भाग लेना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)] सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं,		उनमें भाग लेना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं,

		निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पिळ्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पिळ्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशियत वर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ): कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना । [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है । [अधिनियम की धारा 3(2)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्टत किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना । [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	नि:शक्तता । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिट विभिन्न नि:शक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत । अधिसूचना की एक प्रति उपावंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ख) जहां अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है ।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है ।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

r		T
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:
		(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत ;
		(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:
		(i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर ।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष ।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा:
		(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुजेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध;
		(ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण । बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा ;
		(iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना ।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"
<u> </u>	I .	ı

[फा. सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April, 2016

- **G.S.R. 424 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
- '(b) " dependent" means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for support and maintenance; '.
- 3. In the said rules, in rule 4, —
- (a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-
- " (1) The State Government, on the recommendation of the District Magistrate, shall prepare for each District a panel of such number of eminent senior advocates who have been in practice for not less than seven years, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts.
- (1A) The State Government in consultation with the Director Prosecution or in charge of the prosecution, shall also specify a panel of such number of Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts, as the case may be.
- (1B) Both the panels referred to in sub-rule (1) and sub-rule (1A) shall be notified in the Official Gazette of the State and shall remain in force for a period of three years. ";
- (b) in sub-rule (2) , for the words "Special Public Prosecutors", the words "Special Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors" shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3) , for the words " a Special Public Prosecutor", the words " a Special Public Prosecutor or an Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted;
- (d) for sub-rule (4) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- " (4) The District Magistrate and the officer-in-charge of the prosecution at the District level, shall review,—
 - (a) the position of cases registered under the Act;

- (b) the implementation of the rights of victims and witnesses, specified under the provisions of Chapter IV A of the Act,
- and submit a monthly report on or before 20th day of each subsequent month to the Director of Prosecution and the State Government, which shall specify the actions taken or proposed to be taken in respect of investigation and prosecution of each case. ";
- (e) in sub-rule (5), for the words "conducting cases in the Special Courts", the words "conducting cases in the Special Courts or Exclusive Special Courts" shall be substituted;
- (f) in sub-rule (6), for the words "Special Public Prosecutor", the words "Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted.
- 4. In the said rules, in rule 7, —
- (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
- "(2) The investigating officer so appointed under sub-rule (1) shall complete the investigation on top priority, submit the report to the Superintendent of Police, who in turn shall immediately forward the report to the Director General of Police or Commissioner of Police of the State Government, and the officer in- charge of the concerned police station shall file the charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days (the period is inclusive of investigation and filing of charge-sheet).
- (2A) The delay, if any, in investigation or filing of charge-sheet in accordance with sub-rule (2) shall be explained in writing by the investigating officer.";
- (b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- " (3) The Secretary, Home Department and the Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department (the name of the Department may vary from State to State) of the State Government or Union territory Administration, Director of Prosecution, the officer in-charge of Prosecution and the Director General of Police or the Commissioner of Police in-charge of the concerned State or Union territory shall review by the end of every quarter the position of all investigations done by the investigating officer. ".
- 5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (via) informing the nodal officer and the concerned District Magistrates about implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IV A of the Act;".
- 6. In the said rules, in rule 9, after clause (vi), the following clause shall be inserted namely:-
- " (vii) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA the Act. ".
- 7. In the said rules, in rule 10, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (iv) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA of the Act, in the identified areas. ".

- 8. In the said rules, in rule 12, —
- (a) for sub-rule (4), the following shall be substituted , namely:-
- " (4) The District Magistrate or the Sub- Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall make necessary administrative and other arrangements and provide relief in cash or in kind or both within seven days to the victims of atrocity, their family members and dependents according to the scale as provided in Annexure-I read with Annexure-II of the Schedule annexed to these rules and such immediate relief shall also include food, water, clothing, shelter, medical aid, transport facilities and other essential items.
- (4A) For immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide the relief amount as specified in sub-rule (4), the concerned State Government or Union territory Administration may provide necessary authorisation and powers to the District Magistrate.
- (4B) The Special Court or the Exclusive Special Court may also order socio-economic rehabilitation during investigation, inquiry and trial, as provided in clause (c) of sub-section 6 of section 15A of the Act. ";
- (b) in sub-rule (7), for the words "Special Court" at both the places where they occur, the words "Special Court or Exclusive Special Court" shall respectively be substituted.
- 9. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-
- "14. SPECIFIC RESPONSIBILITY OF STATE GOVERNMENT.—(1) The State Government shall make necessary provisions in its annual budget for providing relief and rehabilitation facilities to the victims of atrocity, as well as for implementing an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act.
- (2) The State Government shall review at least twice in a calendar year, in the month of January and July the performance of the Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor specified or appointed under section 15 of the Act, various reports received, investigation made and preventive steps taken by the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and the reports in respect of lapses on behalf of the concerned officers. ".
- 10. In the said rules, in rule 15, —
- (i) in sub-rule (1),—
- (A) for the words "shall prepare a model contingency plan for implementing", the words "shall frame and implement a plan to effectively implement" shall be substituted;
- (B) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (aa) an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15 A of Chapter IV A of the Act;

- (ii) in sub-rule (2), for the words " to the Central Government in the Ministry of Welfare", the words " to the Central Government in the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment" shall be substituted.
- 11. In the said rules , for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-
- " 16. CONSTITUTION OF STATE-LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE:
- (1) The State Government shall constitute high power vigilance and monitoring committee of not more than twenty-five members consisting of the following, namely:--
- (i) Chief Minister or Administrator Chairman (in case of a State under President's Rule, the Governor shall be the Chairman);
- (ii) Home Minister, Finance Minister and Minister(s) in-charge of welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Members (in case of a State under the President's Rule, the Advisors shall be Members);
- (iii) all elected Members of Parliament and State Legislative Assembly and Legislative Council from the State belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be Members;
- (iv) Chief Secretary, the Home Secretary, the Director General of Police, Director/Deputy Director, the National Commission for the Scheduled Castes and the National Commission for the Scheduled Tribes shall be Members;
- (v) the Secretary in-charge to the welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be Convener.
- (2) The high power vigilance and monitoring committee shall meet at least twice in a calendar year, in the month of January and July to review the implementation of the provisions of the Act, scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers or agencies responsible for implementing the provisions of the Act and review of various reports received by the State Government including that of the nodal officer and special officer. "
- 12. In the said rules in rule 17, in sub-rule (1), after the words "review the implementation of the provisions of the Act, ", the words " scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, " shall be inserted.
- 13. In the said rules, in rule 17A, in sub-rule(1), after the words, "review the implementation of the provisions of the Act", the words "scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, ", shall be inserted.
- 14. In the said rules, in the Schedule, for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE-I [See rule 12(4)] NORMS FOR RELIEF AMOUNT

Sr. No.	Name of the offence	Minimum amount of relief
(1)	(2)	(3)
1.	Putting any inedible or obnoxious substance [Section 3(1)(a) of the Act]	One lakh rupees to the victim. Payment to then victim be made as follows:
2.	Dumping excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance [Section 3(1)(b) of the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR) stage for serial numbers (2) and (3) and 25 percent at FIR stage for serial numbers (1), (4)
3.	Dumping excreta, waste matter, carcasses with intent to cause injury, insult or annoyance [Section 3(1)(c) of the Act]	and (5); (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
4.	Garlanding with footwear or parading naked or semi-naked[Section 3(1)(d) of the Act]	the court; (iii) 40 per cent. when the accused are convicted
5.	Forcibly committing acts such as removing clothes, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body [Section 3(1)(e) of the Act]	by the lower court for serial numbers (2) and (3) and likewise 25 percent for serial numbers (1), (4) and (5).
6.	Wrongful occupation or cultivation of land [Section 3(1)(f) of the Act]	One lakh rupees to the victim. The land or premises or water supply or irrigation facility shall be restored where necessary at Government cost
7.	Wrongful dispossession of land or premises or interfering with the rights, including forest rights. [Section 3(1)(g) of the Act]	by the concerned State Government or Union territory Administration. Payment to the victim be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.

8.	Begar or other forms of forced or bonded labour [Section 3(1)(h) of the Act]	One lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
9.	Compelling to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves [Section 3(1)(i) of the Act]	(i) Payment of 25 per cent. First Information Report (FIR) stage;
10.	Making a member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes to do manual scavenging or employing him for such purpose [Section 3(1)(j) of the Act]	(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
11.	Performing, or promoting dedication of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman as a devadasi [Section 3(1)(k) of the Act]	
12.	Prevention from voting, filing nomination [Section 3(1)(1) of the Act]	Eighty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows:
13.	Forcing, intimidating or obstructing a holder of office of Panchayat or Municipality from performing duties [Section 3(1)(m) of the Act]	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
14.	After poll violence and imposition of social and economic boycott [Section 3(1)(n) of the Act]	the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
15.	Committing any offence under this Act for having voted or not having voted for a particular candidate [Section 3(1)(o) of the Act]	
16.	Instituting false, malicious or vexatious legal proceedings [Section 3(1)(p) of the Act]	Eighty-five thousand rupees to the victim or reimbursement of actual legal expenses and damages, whichever is less. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;

		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
17.	Giving false and frivolous information to a public servant [Section 3(1)(q) of the Act]	One lakh rupees to the victim or reimbursement of actual legal expenses and damages, whichever is less. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
18.	Intentional insult or intimidation to humiliate in any place within public view [Section 3(1)(r) of the Act]	One lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
19.	Abusing by caste name in any place within public view [Section 3(1)(s) of the Act]	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;
20.	Destroying, damaging or defiling any object held sacred or in high esteem [Section 3(1)(t) of the Act]	(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;
21.	Promoting feelings of enmity, hatred or ill-will [Section 3(1)(u) of the Act]	(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
22.	Disrespecting by words or any other means of any late person held in high esteem [Section 3(1)(v) of the Act]	
23.	Intentionally touching a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman without consent, using acts or gestures, as an act of sexual nature, [Section 3(1)(w) of the Act]	Two lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
24.	Section 326B of the Indian Penal Code (45 of 1860)Voluntarily throwing or	(a) Eight lakh and twenty-five thousand rupees to the victim with burns exceeding and 2 per cent

	attempting to throw acid. [Section 3(2)(va)	and above burns on face or in case of functional
	read with Schedule to the Act]	impairment of eye, ear, nose and mouth and or
		burn injury on body exceeding 30 per cent;
		(b) four lakh and fifteen thousand rupees to the
		victim with burns between 10 per cent. to 30 per
		cent. on the body;
		(c) eighty-five thousand rupees to the victim with
		burns less than 10 per cent. on the body other
		than on face.
		In addition, the State Government or Union
		territory Administration shall take full
		responsibility for the treatment of the victim of
		acid attack.
		The payment in terms of items (a) to (c) are to
		be made as follows:
		(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. after receipt of medical report.
25.	Section 354 of the Indian Penal Code (45 of	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	1860) Assault or criminal force to	made as follows:
	woman with intent to outrage her	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	modesty.	stage;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
	[Section 3(2) (va) read with Schedule to	the court;
	the Act]	(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by
		the lower court.
26.	Section 354A of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860)Sexual harassment and	made as follows:
	punishment for sexual harassment.	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	[Section 32) (va) read with Schedule to	stage;
	the Act]	(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the
		lower court.

27	Cation 254 D at the Tadion Daniel Cade (45	The falls were as to the victim Decrease to be
27.	Section 354 B of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Assault or use of criminal force	made as follows:
	to woman with intent to disrobe [Section	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	stage;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by
		the lower court.
28.	Section 354 C of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Voyeurism. [Section 3(2)(va) read	made as follows:
	with Schedule to the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court.
		(iii) 40 per cent. when the accused are
		convicted by the lower court.
29.	Section 354 D of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Stalking. [Section 3(2)(va) read	made as follows:
	with Schedule to the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 40 per cent. when the accused are
		convicted by the lower court.
30.	Section 376B of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Sexual intercourse by husband	made as follows:
	upon his wife during separation. [Section	(i) 50 per cent. after medical examination and
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	confirmatory medical report;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
31.	Section 376C of the Indian Penal Code (45	Four lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Sexual intercourse by a person	made as follows:
	in authority. [Section 3(2)(va) read with	(i) 50 per cent. after medical examination and
	Schedule to the Act]	confirmatory medical report;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
	1	

		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the
		lower court.
32.	Section 509 of the Indian Penal Code (45 of	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	1860) Word, gesture or act intended to	made as follows:
	insult the modesty of a woman. [Section	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
33.	Fouling or corrupting of water [Section	Full cost of restoration of normal facility,
	3(1)(x) of the Act]	including cleaning when the water is fouled, to be
		borne by the concerned State Government or
		Union territory Administration. In addition, an
		amount of eight lakh twenty-five thousand rupees
		shall be deposited with the District Magistrate for
		creating community assets of the nature to be
		decided by the District Authority in consultation with the Local Body.
34.	Denial of customary right of passage to	Four lakh twenty-five thousand rupees to the
J-1.	a place of public resort or obstruction	victim and cost of restoration of right of passage
	from using or accessing public resort	by the concerned State Government or Union
	[Section 3(1)(y) of the Act]	territory Administration. Payment to be made as
	[500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
35.	Forcing of causing to leave house,	Restoration of the site or right to stay in house,
	village, residence desert place of	village or other place of residence by the
	residence [Section 3(1)(z) of the Act]	concerned State Government or Union territory
		Administration and relief of one lakh rupees to
		the victim and reconstruction of the house at
		Government cost, if destroyed. Payment to be

Act]

made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court. 36. Obstructing or preventing a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to-(A) using common *(A)*: Restoration of the right using common property resources of an area, or burial or property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or cremation ground equally with others or using using any river, stream, spring, well, any river, stream, spring, well, tank, cistern, tank, cistern, water-tap or other watering water-tap or other watering place, or any bathing place, or any bathing *ghat*, any public *ghat*, any public conveyance, any road, or conveyance, any road, or passage passage equally with others, by the concerned [Section 3(1)(za)(A) of the Act] State Government or Union Territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court. *(B)*: Restoration of the right of mounting or (B) mounting or riding bicycles or motor riding bicycles or motor cycles or wearing cycles or wearing footwear or new footwear or new clothes in public places or taking clothes in public places or taking out out wedding procession, or mounting a horse or wedding procession, or mounting a horse any other vehicle during wedding processions, or any other vehicle during wedding equally with others by the concerned State processions [Section 3(1)(za)(B) of the

Government or Union territory Administration and

relief of one lakh rupees to the victim. Payment

to be made as follows:

- (i) Payment of 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;
- (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;
- (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court;
- (*C*) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including *jatras* [Section 3(1)(za)(C) of the Act]
- (C): Restoration of the right of entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out any religious procession or jatras, as is open to the public or other persons professing the same religion, social or cultural processions including *jatras*, equally with other persons, by the concerned State Government or Union territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
- (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage
- (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court.
- (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
- (*D*) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public[Section 3(1)(za)(D) of the Act]
- (D): Restoration of the right of entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public, equally with other persons by the concerned State Government or Union territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
- (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)

		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
	(<i>E</i>) practicing any profession or the	(E): Restoration of the right of practicing any
	carrying on of any occupation, trade or	profession or the carrying on of any occupation,
	business or employment in any job which	trade or business or employment in any job
	other members of the public, or any	which other members of the public, or any
	section thereof, have a right to use or	section thereof, have a right to use or have
	have access to [Section 3(1)(za)(E) of	access to, by the concerned State
	the Act]	Government/Union territory Administration and
	the Act	,
		relief of one lakh rupees to the victim. Payment
		to be made as follows:
		(3) 2
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
37.	Causing physical harm or mental agony	One lakh rupees to the victim and also
	on the allegation of being a witch or	commensurate with the indignity, insult, injury
	practicing witchcraft or being a witch	and defamation suffered by the victim. Payment
	[Section 3(1)(zb) of the Act]	to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
		,

38.	Imposing or threatening a social or	Restoration of provision of all economic and
	economic boycott. [Section 3(1)(zc) of	social services equally with other persons, by the
	the Act]	concerned State Government or Union territory
		Administration and relief of one lakh rupees to
		the victim. To be paid in full when charge sheet
		is sent to the lower court.
39.	Giving or fabricating false evidence	Four lakh fifteen thousand rupees to the victim.
	[Section 3(2)(i) and (ii) of the Act]	Payment to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
40.	Committing offences under the Indian	Four lakh rupees to the victim and or his
	Penal Code (45 of 1860) punishable with	dependents. The amount would vary, if
	imprisonment for a term of ten years or	specifically otherwise provided in this Schedule.
	more [Section 3(2) of the Act]	Payment to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
41.	Committing offences under the Indian	Two lakh rupees to the victim and or his
	Penal Code (45 of 1860) specified in the	dependents. The amount would vary if
	Schedule to the Act punishable with such	specifically otherwise provided in this Schedule.
	punishment as specified under the Indian	Payment to be made as follows:
	Penal Code for such offences[Section	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	3(2) (va) read with the Schedule to the Act]	stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court;
42.	Victimisation at the hands of a public	Two lakh rupees to the victim and or his
	servant[Section 3(2)(vii) of the Act]	dependents. Payment to be made as follows:
L	I .	

		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
43.	Disability. Guidelines for evaluation of	by the lower court.
43.	,	
	various disabilities and procedure for	
	certification as contained in the Ministry	
	of Social Justice and Empowerment	
	Notification No. 16-18/97-NI, dated the	
	1 st June, 2001. A copy of the notification	
	is at Annexure-II.	
	(a) 100 per cent. incapacitation	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to
		the victim. Payment to be made as follows:
		(i) 50 per cent. after medical examination and
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
	(b) where incapacitation is less than 100	Four lakh and fifty thousand rupees to the victim.
	per cent. but more than 50 per cent.	Payment to be made as follows:
	per cent. but more than 50 per cent.	(i) 50 per cent. after medical examination and
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
	(a) whose income situation is less the 50	Two lakh and fifty thousand rupees to the victim.
	(c) where incapacitation is less than 50	Payment to be made as follows:
	per cent.	(i) 50 per cent. after medical examination and
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
4.5		the court.
44.	Rape or Gang rape.	
	(i) Rape[Section 375 of the Indian Penal	Five lakh rupees to the victim. Payment to be
	.,	made as follows:
	Code(45 of 1860)]	made as follows.

		(i) 50 per cent. after medical examination and confirmatory medical report;(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the lower court.
	(ii) Gang rape [Section 376D of the Indian Penal Code(45 of 1860)]	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 50 per cent. after medical examination and confirmatory medical report; (ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the lower court.
45.	Murder or Death.	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 50 per cent. after post mortem report; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court.
46.	Additional relief to victims of murder, death, massacre, rape, gang rape, permanent incapacitation and dacoity.	In addition to relief amounts paid under above items, relief may be arranged within three months of date of atrocity as follows:- (i) Basic Pension to the widow or other dependents of deceased persons belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe amounting to five thousand rupees per month, as applicable to a Government servant of the concerned State Government or Union territory Administration, with admissible dearness allowance and employment to one member of the family of the deceased, and provision of agricultural land, an house, if necessary by outright purchase; (ii) Full cost of the education up to graduation level and maintenance of the children of the victims. Children may be admitted to Ashram

		schools or residential schools, fully funded by the
		Government;
		(iii) Provision of utensils, rice, wheat, dals,
		pulses, etc., for a period of three months.
47.	Complete destruction or burnt houses.	Brick or stone masonary house to be constructed
		or provided at Government cost where it has
		been burnt or destroyed."

[F. No. 11012/1/2016-PCR(Desk)]
AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *Extraordinary, vide* notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 and last amended vide G.S.R. 774(E), dated the 5th November, 2014.